भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4441
मंगलवार, 28 मार्च, 2023/7 चैत्र, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

†**4441. श्रीमती नुसरत जहां:**
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पीएसीएस के सभी कम्प्यूटर कार्य कर रहे हैं और समय-समय पर उनका उन्नयन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): कार्यरत प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) की राज्य-वार सूची **अनुबंध** पर संलग्न है ।

2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में 63,000 कार्यरत पैक्स/लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (LAMPS)/किसान सेवा समितियां (FSS) को कंप्यूटरीकृत करने की एक केन्द्रीय प्रयोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । इस परियोजना में सभी कार्यरत पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया जाएगा।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयां (PMUs) स्थापित की गई हैं । नाबार्ड द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तर के परियोजना सॉफ्टवेयर वेंडर के माध्यम से सॉफ्टवेयर का विकास कार्य आरंभ हो चुका है । परियोजना के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद तथा लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है । पैक्स को दो वर्षों की अवधि के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक सहयोग तंत्र स्थापित किया जाएगा ।

पैक्स में इंस्टॉल किए गए हार्डवेयर के रख-रखाव की जिम्मेदारी परियोजना अवधि की समाप्ति के बाद भी सतत रूप से संबंधित पैक्स, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों की होगी । केन्द्रीय अवसंरचना सुविधा और कॉमन सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण और अद्यतन आवधिक रूप से नाबार्ड द्वारा किया जाएगा ।

*****

अनुबंध

कार्यरत पैक्स* की राज्य-वार सूची

'कार्यरत पैक्स' परिभाषा में ऐसे पैक्स अभिप्रेत होते हैं जिनका 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार संपरीक्षण हो चुका है ।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत पैक्स की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2046
2	अरुणाचल प्रदेश	14
3	असम	775
4	बिहार	3779
5	छत्तीसगढ़	2028
6	गोवा	44
7	गुजरात	6016
8	हरियाणा	646
9	हिमाचल प्रदेश	810
10	झारखंड	1782
11	कर्नाटक	5168
12	केरल	1299
13	मध्य प्रदेश	4536
14	महाराष्ट्र	20788
15	मणिपुर	232
16	मेघालय	128
17	मिज़ोरम	30
18	नागालैंड	150
19	ओडिशा	1239
20	पंजाब	3367
21	राजस्थान	4050
22	सिक्किम	178
23	तमिल नाडु	7 **
24	तेलंगाना	727

25	त्रिपुरा	268
26	उत्तर प्रदेश	2330
27	उत्तराखंड	8
28	पश्चिम बंगाल	4173
	संघ राज्यक्षेत्र	
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41
2	जम्मू और कश्मीर	537
3	लद्दाख	10
4	पुड्डुचेरी	45
5	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	शून्य पैक्स
6	चंडीगढ़	शून्य पैक्स
7	दिल्ली	शून्य पैक्स
8	लक्षद्वीप	शून्य पैक्स
कुल		**67251**

* नाबार्ड द्वारा किया गया सर्वेक्षण

** तमिल नाडु की दशा में, रिपोर्ट की गई 4532 पैक्स की कुल संख्या को 7 इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि राज्य ऋण माफी योजना के संदर्भ में विशेष संपरीक्षण कराए जाने के कारण संपरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रुप नहीं दिया गया है ।